



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 180]

नई दिल्ली, बुधवार, मई 16, 2018/वैशाख 26, 1940

No. 180]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 16, 2018/VAISAKHA 26, 1940

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

निरस्तीकरण आदेश

नई दिल्ली, 16 मई, 2018

प्रकरण सं. ओआई-40/2017

विषय : चीन जन गण के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "मेटा-फेनाइलीन डायामीन 4-सल्फॉनिक एसिड (एमपीडीएसए)" के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच।

सं. 6/35/2017-डीजीएडी—समय-समय पर यथासंशोधित सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 (जिसे यहां आगे अधिनियम भी कहा गया है) तथा समय-समय पर यथासंशोधित उसकी सीमा प्रशुल्क (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, मूल्यांकन तथा संग्रहण और क्षति के निर्धारण के लिए) नियमावली, 1995 (जिसे आगे यहां नियमावली कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए मैसर्स चामुंडा इंडस्ट्रीज, मै. मातृशक्ति इंडस्ट्रीज और मै. वाराही इंडस्ट्रीज (जिसे आगे यहां "याचिकाकर्ता" कहा गया है) ने संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के पाटन तथा परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को क्षति का आरोप लगाते हुए चीन जन गण (जिसे आगे यहां "संबद्ध देश" कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "मेटा-फेनाइलीन डायामीन 4-सल्फॉनिक एसिड (एमपीडीएसए)" (जिसे आगे यहां "संबद्ध वस्तु" अथवा "विचाराधीन उत्पाद" कहा गया है) के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच शुरू किए जाने तथा पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के लिए अधिनियम एवं उपर्युक्त नियमावली के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे आगे यहां प्राधिकारी कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत किया था।

2. प्राधिकारी ने उपर्युक्त नियम 5 के उप नियम (5) के अनुसार, जांच की शुरूआत करने की कार्रवाई करने से पूर्व पाटनरोधी आवेदन की प्राप्ति के संबंध में भारत में संबद्ध देश के दूतावास को अधिसूचित किया था।

3. प्राधिकारी ने याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर पाटनरोधी नियमावली के नियम 5 के अनुसार तथाकथित पाटन की मौजूदगी, उसकी मात्रा और प्रभाव का निर्धारण करने और पाटनरोधी शुल्क की ऐसी राशि की सिफारिश करने के लिए, जिसे यदि लगाया जाए तो वह घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करने के लिये पर्याप्त होगी, संबद्ध पाटनरोधी जांच की शुरूआत करते हुए भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित दिनांक 24.01.2018 की अधिसूचना संख्या 6/35/2017-डीजीएडी द्वारा सार्वजनिक सूचना जारी की थी।

4. प्राधिकारी ने विश्लेषण करने के लिए अप्रैल, 2016 से जून, 2017 (15 माह) को जांच की अवधि (पीओआई) के रूप में माना। क्षति विश्लेषण के संदर्भ में प्रवृत्तियों की जाँच के लिए अवधियों में अप्रैल, 2013 - मार्च, 2014, अप्रैल, 2014 - मार्च, 2015, अप्रैल, 2015 - मार्च, 2016 और जांच की अवधि को शामिल किया गया है।

5. और यतः प्राधिकारी ने जांच अवधि तथा पूर्ववर्ती वर्षों के लिए संबद्ध वस्तु की मात्रा और मूल्य का निर्धारण करने हेतु डीजीसीआईएडएस से प्राप्त सौदे-वार आयात आंकड़ों पर विश्वास किया है।

6. प्राधिकारी ने जांच की शुरुआत के बाद भारत में संबद्ध देश के दूतावास, संबद्ध देश के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं तथा याचिकाकर्ताओं द्वारा उपलब्ध कराए गए पतों के अनुसार घरेलू उद्योग को जांच की शुरुआत की प्रतियां भेजीं और पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(2) के अनुसार जांच की शुरुआत की अधिसूचना के 40 दिनों के भीतर लिखित में अपने विचार प्रस्तुत करने का अनुरोध किया। प्राधिकारी द्वारा जहां भी आवश्यकता थी, ऐसे अनुरोध प्रस्तुत करने के लिए आवश्यक समय विस्तार भी दिया गया।

7. प्राधिकारी ने उपर्युक्त नियमावली के नियम 6(3) के अनुसार, भारत में संबद्ध देश के दूतावास को तथा ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को आवेदन के अगोपनीय रूपांतर की प्रतियां उपलब्ध कराई। अन्य हितबद्ध पक्षकारों को भी, जहां अनुरोध किया गया था, आवेदन की प्रति उपलब्ध कराई गई थी। भारत में संबद्ध देश के दूतावास से यह भी अनुरोध किया गया था कि वे अपने देश के निर्यातकों/उत्पादकों को सलाह दें कि वे निर्धारित समय-सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर दें।

8. जांच की शुरुआत के बाद तथा 31.01.2018 को संबद्ध वस्तु के सभी उत्पादकों/निर्यातकों को यह सूचित किया गया था कि संगत सूचना निर्यातक/आयातक प्रश्नावली में अलग-अलग दी जानी चाहिए। प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार संबद्ध देश के 3 ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों से संगत सूचना प्राप्त करने के लिए उन्हें प्रश्नावलियां भेजी थीं।

9. अधिसूचना की शुरुआत और सूचना के उत्तर में संबद्ध देश के 9 निर्यातकों/उत्पादकों ने निर्यातिक प्रश्नावली के उत्तर प्रस्तुत करके प्राधिकारी को उत्तर दिए हैं।

10. आवश्यक सूचना मंगाते हुए भारत में संबद्ध वस्तु के 24 ज्ञात आयातकों/ प्रयोक्ताओं को भी प्रश्नावलियां भेजी गई थीं। 3 आयातकों/प्रयोक्ताओं ने आयातक प्रश्नावली के उत्तर दायर करते हुए उत्तर दिया।

11. प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निरीक्षण के लिए खुले में रखी गई सार्वजनिक फाइल के रूप में विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के अगोपनीय रूपांतर उपलब्ध कराए।

12. प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(6) के अनुसार, सभी हितबद्ध पक्षकारों को मौखिक रूप से अपने विचार प्रस्तुत करने के अवसर प्रदान करने के लिए मौखिक सुनवाई की तारीख भी निर्धारित की थी जो कि 22.05.2018 को आयोजित की जानी थी।

13. घरेलू उद्योग ने नीचे दिए गए कारणों का उल्लेख करते हुए अपने दिनांक 07.05.2018 के पत्र (दिनांक 11.05.2018 को प्राप्त) के जरिए पाटनरोधी नियमावली के नियम 14(क) के तहत वर्तमान जांच को रद्द करने का अनुरोध किया है:

क. उनके ग्राहक इस बात से प्रसन्न नहीं हैं कि उन्होंने पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने हेतु अनुरोध किया है और वे अपने ग्राहकों के साथ इस सीमा तक अपने संबंध खराब नहीं करना चाहते जिससे कि उन्हें पाटनरोधी शुल्क अधिरोपित करवाने के अपने प्रयासों के परिणामस्वरूप अपने ग्राहकों को गंवाना पड़े।

ख. वे एक लघु आकार वाली कंपनी हैं और सरकार की व्यापक अपेक्षाओं को पूरा करने में उन्हें कठिनाई हो रही है तथा यह पूरी प्रक्रिया उन्हें समय गंवाने वाली प्रतीत हो रही है। लगने वाले समय एवं प्रक्रिया को देखते हुए उन्हें अपने ग्राहकों को गंवा देने का भय है।

14. प्राधिकारी निम्नलिखित रूप में पठित पाटनरोधी नियमावली के नियम 14(क) को नोट करते हैं।

14. जांच को रद्द करना – निर्दिष्ट प्राधिकारी एक सार्वजनिक सूचना जारी करके तत्काल ही किसी जांच को रद्द करेंगे, यदि –

(क) उन्हें प्रभावित घरेलू उद्योग, जिसके कहने पर जांच की शुरुआत की गई थी, की ओर से ऐसा करने के लिए लिखित में अनुरोध प्राप्त होता है।

15. तथापि, प्राधिकारी ने नोट किया है कि याचिका को रद्द करने के लिए घरेलू उद्योग द्वारा दिए गए कारण का कोई ठोस आधार नहीं है क्योंकि पाटनरोधी कार्रवाई का उद्देश्य भारत में उपभोक्ताओं के हितों को नुकसान पहुंचाना नहीं है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि ऐसा कोई अनुचित व्यापार न हो जिससे घरेलू उद्योग भारत के घरेलू बाजार में लाभवंचित रहने की स्थिति में आ जाए। इसके अतिरिक्त, अनुपालन की जाने वाली प्रक्रियाएं सरल हैं और उन्हें घरेलू उद्योग सहित संबंधित हितबद्ध पक्षकारों के विभिन्न दावों से संबंधित तथ्यपरक निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए तैयार किया गया है।

16. जहां तक प्रक्रिया में लिए जाने वाले समय का संबंध है, प्राधिकारी का प्रयास समग्र प्रक्रिया को किसी भी राष्ट्रीय व्यापार रक्षा अभिकरण द्वारा लिए जाने वाले कम से कम समय में पूरा करने का है। इस विशिष्ट मामले में प्राधिकारी ने इस बात को समझते हुए कि याचिकाकर्ता लघु वस्तु-थेट्र है और इसलिए किसी अनुचित व्यापार से उस पर अधिक प्रभाव पड़ने की संभावना है, जांच की प्रक्रिया को तीव्रतर गति से पूरा करते हुए उसे जांच की शुरूआत की तारीख से आठ माह के भीतर पूरा किया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि याचिका को उस चरण पर वापस लिए जाने का अनुरोध, जहां प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत सूचना/आंकड़ों के उनके फैक्टरी परिसर में वास्तविक सत्यापन किए जाने के प्रयोजनार्थ उनकी सुविधानुसार तारीख हेतु अनुरोध किया है, से यह स्पष्ट नहीं है कि प्राधिकारी द्वारा ऐसे सत्यापन को याचिकाकर्ता द्वारा दुर्व्यह क्यों माना गया है।

17. तथापि, प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी नियमावली के नियम 14(क) में एक बार जांच की समाप्ति हेतु घरेलू उद्योग द्वारा लिखित में अनुरोध प्रस्तुत किए जाने के बाद इस मामले में प्राधिकारी को कोई विवेकाधिकार प्रदान नहीं किया गया है।

18. तदनुसार, पाटनरोधी नियमावली के नियम 14(क) तथा तीनों याचिकाकर्ताओं के अनुरोध के मद्देनजर प्राधिकारी एतद्वारा अधिसूचना संख्या 6/35/2017-डीजीएडी के जरिए दिनांक 24.01.2018 को शुरू की गई चीन जन गण के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "मेटा-फेनाइलीन डायामीन 4-सल्फॉनिक एसिड (एमपीडीएसए)" के आयातों के संबंध में वर्तमान पाटनरोधी जांच को रद्द करते हैं।

सुनील कुमार, अपर सचिव एवं निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)

TERMINATION ORDER

New Delhi, the 16th May, 2018

Case No. OI-40/2017

Subject : Anti-Dumping investigation on imports of “Meta-Phenylene Diamene-4-Sulphonic Acid (MPDSA)” originating in or exported from People’s Republic of China.

No. 6/35/2017-DGAD.—Having regard to the Customs Tariff Act 1975 as amended from time to time (hereinafter also referred to as the Act) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the Rules) thereof, M/s Chamunda Industries, M/s Matrushakti Industries and M/s Varahi Industries (hereinafter referred to as “the petitioners”) had filed an application before the Designated Authority (hereinafter also referred to as the Authority) in accordance with the Act and Rule *supra* for initiation of anti-dumping investigation and imposition of anti-dumping duties concerning imports of “Meta-Phenylene Diamene-4-Sulphonic Acid (MPDSA)” (hereinafter also referred to as the subject goods or product under consideration), originating in or exported from China PR, (hereinafter also referred to as the subject country) alleging dumping of subject goods from subject country and consequent injury to the domestic industry.

2. The Authority notified the Embassy of the subject country in India about the receipt of the anti-dumping application before proceeding to initiate the investigation in accordance with Sub-rule (5) of Rule 5 *supra*.

3. The Authority on the basis of *prima facie* evidence submitted by the petitioners, issued a public notice vide Notification No.6/35/2017-DGAD dated 24.01.2018, published in the Gazette of India, Extraordinary, initiating the subject anti-dumping investigation in accordance with the Rule 5 of the AD Rules, to determine the existence, degree and effect of the alleged dumping and to recommend the amount of anti-dumping duty, which, if levied, would be adequate to remove the injury to the domestic industry.

4. The Authority considered April 2016 to June 2017 (15 months) as the POI (Period of Investigation) to undertake analysis. For the examination of trends, in the context of injury analysis, the periods covered included Apr'13-Mar'14, Apr'14-Mar'15, Apr'15-Mar'16 and the period of investigation.

5. And whereas, the Authority has relied upon the transaction wise import data obtained from DGCI&S, for determining the volume and value of import of subject goods for the POI and previous years.

6. The Authority post-initiation sent copies of the initiation notification to the Embassy of the subject country in India, known producers/exporters from the subject country, known importers/users and the domestic industry as per the addresses made available by the petitioners and requested them to make their views known in writing within 40 days of the initiation notification as per Rule 6(2) of the AD Rules. Necessary extensions to file such submissions wherever warranted was also granted by the Authority.

7. The Authority provided copies of the non-confidential version of the application to the known producers/ exporters and to the Embassy of the subject country in India in accordance with Rule 6(3) of the Rules supra. A copy of the application was also provided to other interested parties, wherever requested. The Embassy of the subject country in India was also requested to advise its domestic exporters/ producers to respond to the questionnaire within the prescribed time limit.

8. Subsequent to initiation and on 31.1.2018, it was communicated to all the producers/ exporters of the subject goods that the relevant information should be provided separately in exporters/ importer's questionnaires. The Authority sent questionnaires to elicit relevant information to 3 known producers/ exporters in subject country in accordance with Rule 6(4) of the AD Rules;

9. In response to the initiation notification and intimation, 9 exporters/ producers from subject country responded to the Authority by filing Exporter's Questionnaire Response.

10. Questionnaire links were also sent to 24 known importers/ users of subject goods in India calling for necessary information. 3 importers/ users responded by filing Importer Questionnaire responses.

11. The Authority made available non-confidential version of the evidences presented by various interested parties in the form of a public file kept open for inspection by the interested parties.

12. The Authority, in accordance with Rule 6(6) of the AD Rules, to provide opportunity to all interested parties to present their views orally, had also fixed a date of Oral hearing which was supposed to be held on 22.05.2018.

13. The request to terminate the present investigation has been made by the domestic industry under Rule 14(a) of the AD Rule vide its letter dated 07/05/2018 (delivered on 11/05/2018) citing the following reasons:

- a. Their customers are not happy with them and in fact are quite upset with their decision to seek anti-dumping duties and they do not wish to spoil relationships with their customers to such an extent where they might lose their customers in their effort to get duties imposed.
- b. They are quite a small sized company and are finding it difficult to meet the elaborate requirements of the government and find the entire process quite time consuming. In view of the time and process that was being taken, they are afraid of losing their customers.

14. The Authority notes that the Rule 14(a) of the Anti-Dumping Rules read as under:

"Rule 14. Termination of investigation. - The designated authority shall, by issue of a public notice, terminate an investigation immediately if –

(a) it receives a request in writing for doing so from or on behalf of the domestic industry affected, at whose instance the investigation was initiated;"

15. The Authority, however, notes that the reason cited by the domestic industry for termination of the petition appears to have little merit as the anti-dumping action does not seek to hurt the interests of the consumers in India. It only seeks to ensure that there is no unfair trade whereby the domestic industry is placed at a position of disadvantage in India's domestic market. Further, the procedures followed are simple and designed to come to a factual conclusion relating to the various claims of the concerned interested parties, including the domestic industry.

16. Regarding the time taken, the effort of the Authority is to complete investigations in the shortest period taken by any national trade defence agency. In this specific case, the Authority has only fast-tracked the investigation process to complete it within eight months from the date of initiation, recognising that the petitioners are from the small scale sector and therefore more susceptible to any possible unfair trade. The Authority notes that the petitioners have requested the withdrawal of their petition at a stage where the Authority sought its convenience for a physical verification of the information/ data submitted by it, at its factory premises, it is not clear to the Authority why such a verification should be considered onerous by the petitioners.

17. However, the Authority notes that Rule 14(a) of the Anti-Dumping Rules does not grant any discretion to the Authority in the matter of termination of investigation, once the domestic industry files a written request for termination of the investigation.

18. Accordingly, in view of the request of the three petitioners and the provision in Rule 14(a) of the Anti-Dumping Rules, the Authority hereby terminates the present anti-dumping investigation concerning imports of “Meta-Phenylene Diamene-4-Sulphonic Acid (MPDSA)” originating in or exported from People’s Republic of China initiated on 24/01/2018 vide Notification No.6/35/2017-DGAD.

SUNIL KUMAR, Addl. Secy. & Designated Authority